Recommendation of Khan Committee on Privatisation of Telecom Department

346. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the main recommendations of the Khan Committee to privatise Telecommunication Department for converting it into a private body on the lines of British Telecom;

(b) what is Government's response to each of the recommendations of the Committee; and

(c) what is the present position and Government policy in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI SUKH RAM): (a) The Khan Committee has recommended the conversion of status of the Department of Telecommunications, for eventual conversion of operating unit of Department of Telecommunications into a private body on the lines of British Telecom. The main recommendations are as follows:

(i) Formation of a holding company with Headquarters at Delhi.

(ii) A Long distance corporation.

(iii) A metro Corporation encompassing the 4 metro cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras.

(iv) India Telecom, North for 14 Telecom Circles viz. Jammu and Kashmir Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya pradesh, Uttar Pradesh (East), Uttar Pradesh (west), Bihar, West Bengal, Orissa, Assam, North East and Gujarat.

(v) India Telecom. South for 5 Telecom. Circles viz. Maharashtra, Andhra pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka.

(b) & (c) the recommendations of Khan Committee are presently under consideration.

Setting up of Shipbreaking Yard in Orissa

347. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal to set up a ship breaking yard in Orissa;

(b) whether it is a fact that the above proposal has been pending since long;

(c) if so, the reasons for the delay in implementation the above proposal;

(d) whether the above proposal is expected to be implemented during the current financial year; and

(e) if so, the steps taken in that direction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

और अधिक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का खोला जाना

348. **श्री ईशदत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में और अधिक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्यों की सरकारों द्वारा भी इस संबंध में कुछ प्रस्ताव भेजे गये हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि नया पासपोर्ट कार्यालय उन्हीं क्षेत्रों/नगरों में स्थित होना चाहिए जहां एक वर्ष में 50,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हों। नए पासपोर्ट कार्यालयों का खोला जाना कुछ मानदण्डों पर आधारित है जैसे कि कार्य की मात्रा और सरकार के पास उपलब्ध संसाधन। हमारा अनुभव यह है कि नए पासपोर्ट कार्यालय खोल देने मात्र से सेवाओं में सुधार नहीं होता जब तक आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा कार्मिक उपलब्ध न हों।

गुजरात के जामनगर जिले में मोटी खावडी स्थान में गैस-आधारित परियोजनाओं को गैस का आवंटन

349. **श्री कनक सिंह मोहन-सिंह मंगरोला:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जामनगर जिले में मोटी खावडी स्थान पर निजी पार्टियों/कम्पनियों द्वारा स्थापित की जाने वाली गैस आधारित परियोजनाओं को कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का आवंटन किया गया;

(ख) क्या सरकार ने गैस के आवंटन के लिये कुछ मानदंड अपनाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) गुजरात में जामनगर जिले के मोटी खावडी में किसी भी परियोजना के संबंध में गैस का कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) गैस के उपयोग को इष्टतम करने के लिए गैस का आवंटन विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों के संबंध में वरीयता के अधीन सामान्यतया गैस उपयोग के आरोपित आर्थिक मूल्य पर आधारित होता है।

(घ) और (ङ) राज्य में विद्युत और अन्य परियोजनाओं के लिए गैस के आवंटन के संबंध में गुजरात सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। गुजरात में परियोजनाओं को 23.24 एमएमएससीएम प्रतिदिन आवंटित किया गया है। चूंकि उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस पूरी तरह से आवंटित है, इसलिए वर्तमान समय में और अधिक आवंटन करना व्यवहार्य नहीं है।

Telephone Connections Sanctioned to Surat City

350. SHRI KANAKSINGH MOHANSINGH MANGROLA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) what is the number of telephone connections sanctioned for Surat Telephones for the Calendar years 1991, 1992, 1993, 1994 and up to 30th June, 1995;

(b) whether any criteria for the need of telephone connections for Surat city were fixed while sanctioning those connections; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI SUKH RAM): (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Purchase of Mirage Aircraft by Pakistan from France

351. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Pakistan intends to purchase Mirage combat aircrafts from France;

(b) whether the Union Government